

>

Title: Need to take steps for setting up of a petroleum refinery in Rajasthan.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दोसा): राज्य में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार मिलते हैं। यहां खनिज तेल का उत्पादन 29 अगस्त, 2009 को प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 1,25,000 बैरल प्रतिदिन हो जायेगा। देश के बड़े राज्यों में राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य है, जहाँ रिफाइनरी नहीं है। यहां के लोगों की अपेक्षा है कि राज्य में शीघ्र ही रिफाइनरी स्थापित हो ताकि राज्य के निवासियों को मूल्य संवर्धन तथा रोजगार का लाभ मिल सके। राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन केन्द्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री एस.सी. त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी। समिति ने बाड़मेर में प्रथम चरण में 4.5 से 6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने की अनुशंसा की।

राज्य सरकार द्वारा त्रिपाठी कमेटी की सभी अनुशंसाएं मान ली गई हैं तथा ओ.एन.जी.सी. द्वारा चाही गई अतिरिक्त वित्तीय सियायतें भी देने की पेशकश की है। राज्य सरकार द्वारा 7 फरवरी, 2011 को बीपीसीएल के साथ रिफाइनरी उत्पादों के विपणन हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर राजस्थान रिफाइनरी को उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का आग्रह किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने राज्य सरकार के साथ रिफाइनरी परियोजना में सहभागिता की पेशकश की है।

अतः केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय राजस्थान रिफाइनरी को बाड़मेर ब्लॉक से कच्चा तेल खरीदने हेतु नामित करें तथा कूड उत्पादन 4.5 एम.एम.टी.पी.ए. से कम होने की स्थिति में आयात हेतु बाड़मेर-सलाया पाइप लाइन के उपयोग की स्वीकृति प्रदान करें। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ओ.एन.जी.सी. को मुख्य प्रमोटर (69 प्रतिशत सहभागिता) के रूप में बाड़मेर रिफाइनरी स्थापित करने को कहे। राज्य सरकार 26 प्रतिशत सहभागिता इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा की जायेगी।
